भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या – 429

(जिसका उत्तर गुरुवार, 25 अप्रैल, 2013/5 वैशाख, 1935 (शक) को दिया गया)

वित्तीय धोखाधड़ी

*429. **श्री आनंद प्रकाश परांजपे :**

श्री एस. अलागिरी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को सांविधिक दर्जा/शक्तियां देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक कंपनी-वार कितने मामले गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को सौंपे गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कंपनी-वार कितने मामलों की जांच की गई और उन पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) क्या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय का धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए कोई पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री सचिन पायलट)

(क) से (ड.) : एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है।

*****

दिनांक 25.04.2013 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 429 के भाग (क) से (ङ) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जी हां, सरकार का गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को सांविधिक दर्जा देने का प्रस्ताव है और तदनुसार कंपनी विधेयक, 2012 के खंड 211 में समर्थकारी प्रावधान शामिल किए गए हैं।

सांविधिक दर्जा देने के अतिरिक्त गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के कार्यकरण से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान, जिन्हें कंपनी विधेयक, 2012 में प्रस्तावित किया गया है, इस प्रकार हैं:-

- "धोखाधड़ी" को परिभाषित करना और संज्ञेय बनाना;
- गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और सांविधिक मान्यता प्राप्त अन्य जांच एजेंसियों के मध्य समन्वय तंत्र;
- गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की जांच रिपोर्ट को किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय में दायर जांच रिपोर्ट के समकक्ष माना जाना;
- कुछ अपराधों के लिए गिरफ्तारी का अधिकार;

(ग) और (घ): पिछले तीन वर्षों (2010-11, 2011-12 और 2012-13) के दौरान गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को 64 मामले भेजे गए; कंपनी-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान 55 मामलों में जांच पूरी कर ली गई है; कंपनी-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-II** में दिए गए हैं।

55 मामलों, जिनमें मंत्रालय द्वारा जांच का आदेश दिया गया था, में से 25 मामलों में आदेश विभिन्न उच्च न्यायालयों के जांच के निदेशों के आधार पर दिया गया। उच्च न्यायालयों द्वारा भेजे गए अधिकांश मामलों में जांच के लिए विशेष मुद्दे भेजे गए और की गई कार्रवाई न्यायालयों को जांच रिपोर्ट दायर करने तक सीमित थी। जांच रिपोर्टों पर कार्रवाई करना उच्च न्यायालय का विशेषाधिकार है। तथापि, कानून का उल्लंघन होने पर इन रिपोर्टों के निष्कर्षों पर मंत्रालय भी निदेश जारी करता है।

मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 235 के अंतर्गत भेजे गए मामलों में अभियोजन की स्वीकृति, जहां कहीं आवश्यक हो, दी जाती है। 20 मामलों में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 79 शिकायतें और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 के अंतर्गत 6 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

(ङ): जी हां। कारपोरेट क्षेत्र में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का पहले से पता लगाने के लिए पूर्व चेतावनी संकेतों के लिए एक "धोखाधड़ी पूर्वानुमान मॉडल" तैयार करने पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय सक्रियता से विचार कर रहा है।

धोखाधड़ी पूर्वानुमान मॉडल के लिए व्यापक ढांचा तैयार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञों के साथ एक उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन किया गया है। विचारार्थ विषयों में प्रायोगिक परियोजना के परीक्षण हेतु समय-सीमा सहित कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करना शामिल है।

संचालन समिति ने अपनी प्रारूप रिपोर्ट गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को प्रस्तुत कर दी है जिस पर विचार किया जा रहा है। आशा है कि मॉडल का प्रायोगिक परीक्षण चालू वित्त वर्ष (2013-14) में कर लिया जाएगा। मॉडल का विकास करना एक अत्यधिक पुनरावृत्तीय प्रक्रिया है, अत: प्रयोग "धोखाधड़ी प्रवणता मॉडल" के रूप में शुरू किया जाएगा जिसे समय के साथ भविष्यसूचक में विकसित किया जाएगा।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 25.04.2013 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 429 के भाग (ग) और (घ) तक के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष – 2010-11

क्र.सं.	कंपनी का नाम	जांच के आदेश की तिथि	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि/वर्तमान स्थिति
1	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	28/05/2010	09/03/2012
2	सुभिक्षा ट्रेडिंग सर्विसेज लि.	23/07/2010	कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जांच वापस लिया गया तथा पुन: 18.10.2012 को जांच आदेश दिए गए। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2013 से आठ सप्ताह के लिए रोक लगाई गई। रोक विद्यमान है क्योंकि यह मामला अभी सुनवाई हेतु आना शेष है।
3	गोल्डक्वेस्ट इंटरनेशनल प्रा. लि.	28/07/2010	05/03/2012
4	क्वेस्टनेट एंटरप्राइसेज इंडिया प्रा. लि.	28/07/2010	05/03/2012
5	जयंत विटामिंस लि.	11/08/2010	29.05.2012
6	सिटी लिमोजिंस (इंडिया) लि.	07/10/2010	30.01.2012

वर्ष – 2011-12

7	अंबुजा सीमेंट्स लि.	02/06/2011	26/07/2011
8	एसीसी लि.	02/06/2011	26/07/2011
9	अल्ट्राटेक सीमेंट लि.	02/06/2011	2707/2011
10	मैसर्स एच.एम.डाइंग लि. (परिसमापधीन)	27/07/2011	21/02/2012
11	मैसर्स डाइमेनशन्स इंवेस्टमेंट एंड सिक्युरिटीज लि. (परिसमापधीन)	09/08/2011	07/03/2012
12	मैसर्स स्पीकएशियाऑनलाइन	10/08/2011 एवं 13/12/2012	प्रगति पर
13	मैसर्स मैटलेक्स सिरेमिक लि. (परिसमापधीन)	05/09/2011	11/01/2012
14	मैसर्स पालामूर एग्रो कॉम्पलेक्स लि. (परिसमापधीन)	13/10/2011	29/02/2012
15	मैसर्स गंगा यमुना फिनवेस्ट प्रा. लि. (परिसमापधीन)	18/10/2011	30/03/2012
16	मैसर्स लक्षीष हैबिटेट्स लि. (परिसमापधीन)	14/12/2011	13/08/2012
17	मैसर्स सावित्री इंडिया लि. (परिसमापधीन)	04/01/2012	14/08/2012
18	मैसर्स जेनसन्स एंड निकोल्सन फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (परिसमापधीन)	02.02.2012	17/08/2012
19	पुष्कर ट्रेडिंग कंपनी लि. (परिसमापधीन)	13.03.2012	31/08/2012

वर्ष – 2012-13

20	त्रिवेणी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लि. (परिसमापधीन)	02.04.2012	06.09.2012
21	सिंह कॉन्ट्रक्टर्स (आई) प्रा. लि. (परिसमापधीन)	11.04.2012	26.09.2012
22	टिम्बर वर्ल्ड रिसॉर्टस एंड प्लान्टेशन प्रा. लि. (परिसमापधीन)	23.04.2012	27.02.2013
23	कुश प्रिंट (पी) लि. (परिसमापधीन)	23.04.2012	05.12.2012
24	केज़न फाईनेंस एंड इनवेस्टमेंट (इंडिया) लि. (परिसमापधीन)	07.05.2012	23.11.2012
25	डीएसएस मोबाइल कम्युनिकेशन्स लि. (परिसमापधीन)	16.05.2012	18.03.2013
26	विजय एसोसिएट्स (अप्रोप्राइटरी कन्सर्न)	17.05.2012	26/07/2012
27	आयुषी बिल्डएस्टेट प्रा. लि.	17.05.2012	18/09/2012
28	मॉव फार्म्स प्रा. लि.	17.05.2012	03/08/2012
29	युसूफ प्रोपर्टीज प्रा. लि.	17.05.2012	30/08/2012
30	साज़ाद प्रोपर्टीज प्रा. लि.	17.05.2012	31/12/2012
31	रिबॉक इंडिया कंपनी (असीमित देयता कंपनी)	29.05.2012	प्रगति पर
32	इंडिपेन्डेंट मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि. (परिसमापधीन)	08.06.2012	19/10/2012
33 34 35 36 37	मैसर्स बेसिल इंटरनेशनल लि. मैसर्स वाम्शी केमिकल्स लि. मैसर्स निक्सील फार्मासुटिकल्स स्पेशिलिटीज लि. एप्लाइन कास्मेटिक्स एंड टॉइलट्रीज़ लि. मैसर्स बेसिल एक्सप्रेस लि.	02.07.2012	प्रगति पर
38 39 40 41 42 43 44 45 46	मैसर्स वैष्णवी कॉरपोरेट कम्युनिकेशन्स प्रा. लि. मैसर्स वैष्णवी एडवायजरी सर्विसेज़ प्रा. लि. मैसर्स लीज़र क्लब्स इंडिया प्रा. लि. मैसर्स क्लैरो कंसल्टेंसी प्रा. लि. मैसर्स मैजिक एयरलाइन प्रा. लि. मैसर्स मानसी एग्रो प्रा. लि. मैसर्स क्राउनमार्ट इंटरनेशनल इंडिया प्रा. लि. मैसर्स विटकॉम कंसल्टिंग प्राइवेट लि. मैसर्स न्यूकॉम कंसल्टिंग प्रा. लि.	09.07.2012	प्रगति पर
47	मैसर्स ऑमवे बिल्ड एस्टेट प्रा. लि.	12.07.2012	02.11.2012
48	मैसर्स एबीसीइंडिया नेटवर्क्स प्रा. लि.	25.07.2012	12.12.2012
49 50 51	मैसर्स यूनीगेटवे 2यू ट्रेडिंग प्रा. लि. मैसर्स यूनीपे 2यू मार्केटिंग प्रा. लि. मैसर्स यूनीपे क्रिएटिव बिजनेस प्रा. लि.	03.08.2012	प्रगति पर

52	मैसर्स यूनीपे 2यू प्रोडक्शन प्रा. लि.		
53 54	मैसर्स बीपीटीपी पार्कलैण्ड्स, फरीदाबाद मैसर्स बीपीटीपी पार्कलैंड प्राइड	03.08.2012	दिनांक 18.03.2013 तक रोक लगाई गई। दिनांक 11.04.2013 को पुनः अधिसूचित किया गया। दिनांक 11.04.2013 के आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय ने दो एफआईआर तथा उससे उत्पन्न कार्यवाहियां रद्द कर दीं। अतः, दोनों मामले उच्च न्यायालय द्वारा वापस ले लिए गए हैं।
55	मैसर्स काइनेमैटिक्स मार्केटिंग (पी) लि.	03.08.2012	01.04.2013
56	मैसर्स लाइफ बिजनेस प्रोजेक्ट प्रा. लि. (श्री भुवनेश चतुर्वेदी तथा अन्य)	14.08.2012	01.03.2013
57	मैसर्स जेनेक्स्ट प्रोमोटर्स प्रा. लि.	30.08.2012	13.12.2012
58	मैसर्स महक व्यापार प्रा. लि.	26.09.2012	21.03.2013
59	मैसर्स एबीडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रकचर लि.	18.10.2012	प्रगति पर
60	मैसर्स अलकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लि.	05.11.2012	7.3.2013 तक रोक लगाई गई। 6.8.2013 तक आगे रोक लगाई गई।
61	मैसर्स डीआर गौर प्रोजेक्ट्रस प्रा. लि.	04.12.2012	प्रगति पर
62	मैसर्स एलांइस निर्माण प्रा. लि. एंड मैसर्स जी.एन. प्रोपर्टीज प्रा. लि.	04.12.2012	दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2012 को जांच आदेश वापस लिया गया।
63	मैसर्स तुलसियात टेक प्रा. लि.	06.03.2013	प्रगति पर
64	मैसर्स सीमलेस आऊटसोर्सिंग एलएलपी		

*****

अनुलग्नक-II

दिनांक 25.04.2013 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 429 के भाग (ग) औ (घ) तक के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई जांच

(2010-11, 2011-12 और 2012-13)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	भेजने वाला	जांच आदेश की तिथि	प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई कार्रवाई करने की तिथि	
1.	निक्को यूको एलायंस क्रेडिट लि.	मंत्रालय	20/06/2008	03.06.2010	• कंपनी अधिनियम के तहत 4 शिकायतें दायर की गईं।। • आईपीसी के तहत 2 शिकायतें दायर की जा रही हैं।
2.	इंफोरमेशन टेक्नोलॉजिज इंडिया लि.	मंत्रालय	16/07/2010	03.09.2010	• कंपनी अधिनियम के तहत 7 शिकायतें दायर की गईं।। • आईपीसी के तहत 6 शिकायतें दायर करने पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई।
3.	पीएसजी डवलपर्स एंड इंजिनियर्स लि.	मंत्रालय	16/05/2008	16/11/2010	• कंपनी अधिनियम के तहत 14 शिकायतें दायर की गईं।। • आईपीसी के तहत 12 शिकायतें दायर की जा रही हैं।
4.	जेनेट सॉफ्टवेयर लि.	मंत्रालय	15/05/2008	21/01/2011	• कंपनी अधिनियम के उल्लंघन के 2 मामलों के संबंध में आरओसी को अपराध शमन के लिए याचिका भेजी गई है। • आईपीसी के अंतर्गत उल्लंघन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु सीबीआई को भेजे गए हैं।
5.	सुगंध एस्टेट एंड	मंत्रालय	16/05/2008	21/01/2011	• कंपनी अधिनियम के

	इंवेस्टमेंट प्रा. लि.				उल्लंघन के 2 मामलों के संबंध में आरओसी को अपराध शमन के लिए याचिका भेजी गई है। • आईपीसी के अंतर्गत उल्लंघन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु सीबीआई को भेजे गए हैं।
6.	अमधी इंवेस्टमेंट्स लि.	मंत्रालय	16/05/2008	21/01/2011	• कंपनी अधिनियम के उल्लंघन के 2 मामलों के संबंध में आरओसी को अपराध शमन के लिए याचिका भेजी गई है। • आईपीसी के अंतर्गत उल्लंघन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु सीबीआई को भेजे गए हैं।
7.	वेलवेट फाइनेंसियल एडवायजर्स प्रा. लि.	मंत्रालय	16/05/2008	21/01/2011	• कंपनी अधिनियम के तहत 4 शिकायतें दायर की गईं।
8.	एवीआई टेलेकम लि.	मंत्रालय	05/05/2008	31/01/2011	• कंपनी अधिनियम के तहत 1 शिकायत दायर की गई
9.	एवीआई पेट्रोलियम लि.	मंत्रालय	05/05/2008	31/01/2011	• कंपनी अधिनियम के तहत 1 शिकायत दायर की गई
10.	एवीआई पैकेजिंग (इंडिया) लि.	मंत्रालय	05/05/2008	31/01/2011	• कंपनी अधिनियम के तहत 1 शिकायत दायर की गई
11.	एएंडआर आयल मिल्स प्रा. लि.	मंत्रालय	05/05/2008	31/01/2011	• कंपनी अधिनियम के तहत 1 शिकायत दायर की गई
12.	ऋषी स्पीनर्स लि.	मंत्रालय	05/05/2008	31/01/2011	कंपनी का नाम हटा दिया गया है।
13.	ऋषी फाइनेंसियल सर्विसेज लि.	मंत्रालय	05/05/2008	31/01/2011	• कंपनी अधिनियम के तहत 1 शिकायत दायर किया गए।

14.	सेसा गोवा लि.	मंत्रालय	23/10/2009	29/04/2011	• कंपनी अधिनियम के तहत 3 शिकायतें दायर की गईं।
15.	सेसा इंडस्ट्रीज लि.	मंत्रालय	23/10/2009	29/04/2011	• कंपनी अधिनियम के तहत 3 शिकायत दायर की गई।
16.	सिस्टम अमेरिका (इंडिया) लि.	मंत्रालय	17/01/2008	16/05/2011	एसएफआईओ का प्रतिवेदन आगे कार्यवाही हेतु प्रवर्तन निदेशालय को अग्रेषित किया गया।
17.	अंबुजा सीमेंट लि.	मंत्रालय	02/06/2011	26/07/2011	एसएफआईओ का प्रतिवेदन उपयुक्त कार्यवाही हेतु सीसीआई को संदर्भित किया गया।
18.	एसीसी	मंत्रालय	02/06/2011	26/07/2011	एसएफआईओ का प्रतिवेदन उपयुक्त कार्यवाही हेतु सीसीआई को संदर्भित किया गया।
19.	अल्ट्राटेक सीमेंट	मंत्रालय	02/06/2011	27/07/2011	एसएफआईओ का प्रतिवेदन उपयुक्त कार्यवाही हेतु सीसीआई को संदर्भित किया गया।
20.	मेगासिटी (बंगलौर) डवलपर्स एंड बिल्डिंग्स लि.	मंत्रालय	17/04/2009	02/08/2011	• कंपनी अधिनियम के तहत 8 शिकायतें दायर की गईं।। • आईपीसी के तहत 6 शिकायतें दायर की गईं।
21.	ऋषी आयल एंड फैट्स लि. (समापनाधीन)	मंत्रालय	05/05/2008	29/12/2011	अभियोजन संस्वीकृत, उच्च न्यायालय के अनुमति की प्रतीक्षा है।
22.	एवीआई शूज लि. (समापनाधीन)	मंत्रालय	**05/05/2008**	**29/12/2011**	अभियोजन संस्वीकृत, उच्च न्यायालय के अनुमति की प्रतीक्षा है।
23.	एवीआई इंडस्ट्रीज लि. (समापनाधीन)	मंत्रालय	**13/05/2009**	**29/12/2011**	संदर्भाधीन विषय एवीआई शूज के प्रतिवेदन में शामिल है।
24.	ऑस्ट्रल कोक एंड प्रोजेक्ट लि.	मंत्रालय	20/01/2010	29/12/2011	• कंपनी अधिनियम के तहत 4 शिकायतें दायर की गई। • आईपीसी के तहत 2 शिकायतें दायर की जा रही हैं।
25.	मैसर्स मेटलेक्स सेरामिक लि. (परिसमापनाधीन)	उच्च न्यायालय	05/09/2011	11/01/2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत
26.	सिटी लिमोजिन्स (इंडिया) लि.	मंत्रालय	07/10/2010	30/01/2012	• कंपनी अधिनियम के तहत 12 शिकायतें दायर की गईं। • आईपीसी के तहत 5 शिकायतें दायर की जा रही हैं।

27.	मैसर्स एचएम डाइंग लि. (परिसमापनाधीन)	उच्च न्यायालय	27/07/2011	21/02/2012	आईपीसी आरोपों को मजबूत करने के लिए अनुपूरक प्रतिवेदन का कार्य प्रगति पर है।
28.	मैसर्स पालामूर एग्रो कॉम्प्लेक्स लि. (परिसमापनाधीन)	उच्च न्यायालय	13/10/2011	29/02/2012	• आईपीसी के तहत 2 शिकायतें दायर की जा रही हैं। • आरओसी, हैदराबाद द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत अभियोजन दायर किए जा रहे हैं।
29.	गोल्डक्वेस्ट इंटरनेशनल प्रा. लि.	मंत्रालय	28/07/2010	05/03/2012	संदर्भ पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय से अनुदेश प्रतिक्षित है।
30.	क्वेस्टनेट इंटरप्राइजेज इंडिया प्रा. लि.	मंत्रालय	28/07/2010	05/03/2012	संदर्भ पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय से अनुदेश प्रतिक्षित है।
31.	डायमेन्सन्स इंवेस्टमेंट एंड सिक्युरीटिज लि. (परिसमापनाधीन)	उच्च न्यायालय	09/08/2011	07/03/2012	• उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। • कंपनी अधिनियम के तहत 2 शिकायतें दायर की जा रही हैं।
32.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक	मंत्रालय	28/05/2010	09/03/2012	कंपनी अधिनियम के तहत 8 शिकायतें दायर की गईं।।
33.	मैसर्स गंगा यमुना फिनवेस्ट प्रा. लि. (परिसमापनाधीन)	उच्च न्यायालय	18/10/2011	30/03/2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
34.	जयंत विटामिंस लि.	मंत्रालय	11/08/2010	29/05/2012	कंपनी अधिनियम के तहत 9 शिकायतें दायर की गईं।
35.	मैसर्स विजय एसोसिएट्स	उच्च न्यायालय	17/05/2012	26/07/2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
36.	मैसर्स मौव फार्म्स प्रा. लि.	उच्च न्यायालय	17.05.2012	03/08/2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
37.	मैसर्स लक्षिश हैबिटेट्स लि. (परिसमापनाधीन)	उच्च न्यायालय	14/12/2011	13/08/2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
38	मैसर्स सावित्री फिनलीज सिक्युरीटिज लि. (परिसमापनाधीन)	उच्च न्यायालय	04/01/2012	14/08/2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

39	मैसर्स जेन्सन एंड निकोल्सन फाइनेंसियल सर्विसेज लि.	उच्च न्यायालय	02/02/2012	17/08/2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
40	युसुफ प्रोपर्टीज प्रा.लि.	उच्च न्यायालय	17.05.2012	30/08/2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
41	पुष्कर ट्रेडिंग कं. लि. (परिसमापनाधीन)	उच्च न्यायालय	13.03.2012	31/08/2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
42	त्रिवेणी इंफ्रॉस्ट्रक्चर डवलपमेंट कं. लि. (परिसमापनाधीन)	उच्च न्यायालय	02.04.2012	06/09/2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
43	आयुषी बिल्डएस्टेट प्रा. लि.	उच्च न्यायालय	17.05.2012	18/09/2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
44	सिंह कंट्रक्टर्स (आई) प्रा. लि. (समापनाधीन)	उच्च न्यायालय	11.04.2012	26/09/2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
45	इंडेपेंडेंट मोबाइल इंफ्रास्टकचर्स (प्रा.) लि. (समापनाधीन)	उच्च न्यायालय	08.06.2012	19/10/2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
46	मैसर्स ओमवे बिल्ड एस्टेट प्रा. लि.	उच्च न्यायालय	12.07.2012	02/11/2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
47	कैजन फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट (इंडिया) लि. (परिसमापनाधीन)	उच्च न्यायालय	07.05.2012	23.11.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
48	कुश प्रींट (प्रा.) लि. (समापनाधीन)	उच्च न्यायालय	23.04.2012	05.12.2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
49	मैसर्स एबीसी इंडिया नेटवर्क प्रा. लि.	उच्च न्यायालय	25.07.2012	12.12.2012	• उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। • कंपनी अधिनियम के तहत 2 शिकायतें दायर की जा रही हैं।
50	मैसर्स जेनेक्स्ट प्रोमोटर्स प्रा. लि.	उच्च न्यायालय	30.08.2012	13.12.2012	• उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। • कंपनी अधिनियम के तहत 17 शिकायतें दायर की जा रही हैं।
51	साजाद प्रोपर्टिज प्रा. लि.	उच्च न्यायालय	17.05.2012	31/12/2012	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
52	टिम्बर वर्ल्ड रीसॉर्ट्स एंड प्लांटेशन प्रा. लि. (समापनाधीन)	उच्च न्यायालय	23.04.2012	27/02/2013	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

53	मैसर्स लाइफ बिजनेस प्रोजेक्ट प्रा. लि. (श्री भुवनेश चतुर्वेदी एंड अन्य)	उच्च न्यायालय	14.08.2012	01/03/2013	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
54	डीएसएस मोबाइल कम्युनिकेशन्स लि. (परिसमापनाधीन)	उच्च न्यायालय	16.05.2012	18.03.2013	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
55	मैसर्स महक व्यापार प्रा. लि.	उच्च न्यायालय	26.09.2012	21.03.2013	उच्च न्यायालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

*****